

विभाग द्वारा सर्वेक्षण/तरमीम के दौरान सामान्यतः मू-सम्पदा मानचित्र बनाने के लिए प्रत्येक सर्वेक्षण को भूमि/धरातल पर पाई जाने वाली सीमाओं को ध्यान में रखकर क्षेत्र पुस्तिका में अंकन करना होता है। क्षेत्र पुस्तिका से मानचित्र तैयार करते समय उन सभी सीमाओं का चिह्न/रेखांकन निर्धारित शीट पर करना होता है, परन्तु इन सीमाओं में कई ऐसी सीमाएँ भी होती हैं जिनको काश्तकार अपनी सुविधा हेतु धरातल पर बना लेता है, लेकिन उन सीमाओं का कोई वैधानिक आधार नहीं होता है, जैसे-एक खेत में चार भाईयों के आपसी बंटवारे से बनाई गई सीमाएँ या किसी अतिक्रमी द्वारा अतिक्रमीत भूमि की सीमाएँ आदि।

इस निमित्त पूर्व में दिये गये आदेशों को निरस्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि भूमि में मू-प्रबन्ध सक्रियताओं के अधीन दी जाने वाली तहसीलों में सर्वे/तरमीम करते समय ऐसी कोई भी सीमा जिनका कि कोई वैधानिक आधार न हो मानचित्र में नहीं दर्शाया जावे। ताबिक मानचित्र एवं जमाबन्दी की सहायता से ऐसा किया जाना सम्भव है। मानचित्र तैयार करते समय केवल वैधानिक सीमाओं को ही पुख्ता किया जावे। अगर मानचित्र में अवांछित सीमाएँ रेखांकित करली गई हैं तो मानचित्र पर सीमाओं को पुख्ता करते समय उन्हें हटा दिया जावे। यह भी ध्यान रखा जावे कि ऐसी अवांछित सीमाओं द्वारा स्वयंजित खेतों के परचे भी वितरित न किये जावें।

विकास कार्यों के क्रिया-व्ययन से धरातल पर यदि कोई झूठ पुख्ता परिवर्तन जैसे-सड़कें, कुएँ, भवन आदि परिवर्तित किये गये हैं तो उनका अंकन/रेखांकन मानचित्र में अवश्य किया जावे।

राजकीय एवं सार्वजनिक भवन, औद्योगिक प्रतिष्ठान, व्यावसायिक व राजकीय भूमि/सिवायक/चरागाह आदि की सीमाओं को पूर्णतः ही दर्शाया जावे। इन आदेशों की पालना किया जाना अनिवार्य है।

॥डा. राजबहादुर सिंह॥

मू-प्रबन्ध आयुक्त,
राजस्थान, जयपुर।

दिनांक:-

क्रमांक-समसंबंधक/

प्रतिलिपि:- १। शासन सचिव, राजस्व को सूचनाार्थ।

२। मू-प्रबन्ध अधिकारी-जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, सीकर, टोंक, अलवर, भरतपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, झुंजरपुर, सिराही, भीलवाड़ा, कोटा को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

मू-प्रबन्ध आयुक्त,
राजस्थान, जयपुर।